वित्तीय संकट से जूझ रहीं उत्तर प्रदेश की निजी चीनी मिलें कर रहीं कर्मचारियों की छंटनी

चीनी मिलों में छंटनी की तलवार

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 21 अगस्त

वित्तीय संकट से जूझ रही उत्तर प्रदेश की निजी चीनी मिलों ने 2014-15 के पेराई सत्र में परिचालन बंद रखने का नोटिस देने के बाद अब कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। बजाज हिंदुस्तान और बलरामपुर समूह सहित सभी बड़ी चीनी कंपनियों ने अपने मौसमी, अस्थायी और संविदा कर्मचारियों को परिचालन बंद रखने के बारे में बताना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब है कि चीनी मिलों को फिलहाल उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है।

इस छंटनी का सबसे ज्यादा असर मजदूरों और सुपरवाइजर स्तर के कर्मचारियों पर पड़ा है, जिनकी मिल के कुल कर्मचारियों में सबसे ज्यादा तादाद होती है। वेज बोर्ड में आने वाले और प्रबंधकीय सहित सभी स्थायी कर्मचारियों को फिलहाल इस छंटनी से अलग रखा गया है।

मिल श्रमिकों में अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल हर स्तर के कर्मचारी शामिल हैं। मिलें जब बंद रहती हैं तो उस दौरान भी मौसमी कर्मचारियों को 50 फीसदी वेतन का भुगतान किया जाता है, जो उन्हें मिल से जोड़े रखने के वास्ते बतौर मुआवजा दिया जाता है। मिलों ने राज्य सरकार द्वारा गन्ने व चीनी की कीमतों को आपस में संबद्ध करने और बीते साल के गन्ने के बकाये के भुगतान के लिए 9 रुपये प्रति क्विंटल देने का वादे को पूरा करने सहित अन्य मांगों पर अमल किए जाने तक पेराई चालू नहीं करने का फैसला किया है। अभी तक सभी बड़ी चीनी मिलों सहित लगभग 66 मिलों ने राज्य सरकार को परिचालन को निलंबित करने का नोटिस दिया है। राज्य में 95 निजी और 23 सहकारी चीनी मिलें हैं। और पेराई सत्र के दौरान लगभग इन मिलों में करीब 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है।

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'परिचालन बंद होने की स्थिति में मिलों द्वारा कर्मचारियों को हटाना एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है।' उन्होंने कहा, 'यदि मिलों को चलाने से खासा आर्थिक नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में मिलें चल नहीं पाएंगी।'

निजी मिलें इस समय 5,000 करोड़ रुपये के गन्ने के बकाये के बोझ से दबी हैं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर रहा है। मिलों की दलील है कि बकाये में सबसे बड़ा योगदान गन्ने की ऊंची कीमतों का है, जिसके चलते संकट पैदा हुआ है।

शुगर टेक्नोलॉजिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसटीएआई) के पूर्व महासचिव ए के शुक्ला ने कहा, 'उत्तर प्रदेश में लगभग 10,000 बेहद कुशल कर्मचारी बेकार बैठे हैं। इससे उद्योग की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।' उन्होंने दावा किया कि स्थायी और अनुंबध पर काम करने वाले प्रबंधकीय और तकनीकी कर्मचारियों को भी जबरन छुट्टी पर जाने को कहा गया है।

उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, 'सरकार को इस समय उद्योग को समर्थन देने के लिए आगे आना चाहिए था लेकिन सरकार मिल मालिकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है।' शुक्ला ने कहा कि मिलों के सामने सीमित विकल्प हैं, इसीलिए इकाइयों को बंद किया जा रहा है और कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश का चीनी उद्योग सालाना 30 हजार करोड़ रुपये का है और यह क्षेत्र कर के रूप में सरकारी खजाने में खासा योगदान करता है।

बढ़ी मुश्किल

- मिलों के बंदी के नोटिस के बाद उत्तर प्रदेश में और गहराया चीनी क्षेत्र का संकट
- मजदूरों और सुपरवाइजर स्तर के कर्मचारियों पर पड़ा सबसे ज्यादा असर
- फिलहाल अस्थायी, अनुंबध और मौसमी कामगारों को ही निकाला जा रहा है

बिजनेस स्टैंडर्ड
22/8/14